डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 के उद्घाटन पर संबोधन *

श्री संजय मल्होत्रा

डिजिटल भुगतान – पृष्ठभूमि और लाभ

भुगतान वाणिज्य की जीवनरेखा हैं, जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को सक्षम बनाते हैं। ये लोगों को जोड़ते हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं। किफायती कीमतों पर त्वरित, सुरक्षित और विश्वसनीय भुगतान एक जीवंत अर्थव्यवस्था का आधार हैं। डिजिटल माध्यमों से भुगतान आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ये उच्च लेनदेन लागत और भौगोलिक सीमाओं[1] जैसी बाधाओं को दूर करके वित्तीय समावेशन को भी गहरा करते हैं। वास्तव में, डिजिटल भुगतान न केवल सुविधाजनक हैं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और विकास का एक शक्तिशाली साधन भी हैं।

डिजिटल भुगतान - सुविधा: उत्पादों का गुलदस्ता

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों को समर्थन प्रदान करता रहा है। इससे ग्राहकों के लिए विकल्प और सुविधा बढ़ी है। हमने ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा) से शुरुआत की। फिर हमने एनईएफ़टी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनएसीएच (यह ई-मैंडेट के लिए है, इसने ईसीएस की जगह ले ली है), एईपीएस, यूपीआई, एनईसीटी आदि की शुरुआत की। हमने यूपीआई पर कई नई सुविधाएँ शुरू की हैं और ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया है। इनमें यूपीआई123पे, यूपीआई लाइट, रूपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करना, सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट के साथ भुगतान मैंडेट को प्रोसेस करना, यूपीआई के लिए क्रेडिट लाइन सक्षम करना, पीपीआई को यूपीआई से लिंक करना आदि शामिल हैं। अपनी विविध विशेषताओं के साथ, यूपीआई हमें एक साधारण क्लिक, टैप या स्कैन से पैसे ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने और खरीदारी करने की सुविधा देता है। हम भुगतान ईकोसिस्टम के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे।

डिजिटल भुगतान – सुरक्षा और संरक्षा

डिजिटल भुगतान प्रणालियों और उनसे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देते हुए, हम भुगतान में सुरक्षा की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते रहे हैं। इसलिए, हमने इस उद्देश्य के लिए कई उपाय किए हैं:

- बहु-कारक प्रमाणीकरण; इंटरनेट और मोबाइल भुगतान ऐप्स और कार्ड भुगतान के लिए सुरक्षा नियंत्रण; कार्ड टोकनाइजेशन (व्यापारियों की प्रणालियों में कार्ड विवरणों के भंडारण को रोकने के लिए), आदि का उद्देश्य हमारे भुगतान ईकोसिस्टम को मजबूत बनाना है।
- हमने ग्राहकों को आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैन्डेट बनाने और समाप्त करने पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाया है।

भुगतान ईकोसिस्टम की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। हाल ही में जारी "डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्रों पर रूपरेखा" और "सीमा पार कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए)" पर मसौदे इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

भुगतान प्रणालियाँ - आगे का रास्ता

आरबीआई के अलावा, सरकार और बैंकों व भुगतान प्रणाली संचालकों जैसे अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों ने भी डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं। हालाँकि इन प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं, जैसा कि डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि से स्पष्ट है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आगे बढ़ते हुए, हम तीन व्यापक क्षेत्रों पर काम करेंगे।

भुगतान प्रणालियाँ - नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट टच विनियम

सबसे पहले, हम भुगतान में नवाचार को प्रोत्साहित करते रहेंगे, जैसा कि सामान्यतः होता है, साथ ही जोखिमों के प्रति

---

* डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 के उद्घाटन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन, 10 मार्च, 2025, आरबीआई, मुंबई।

[1] विश्व बैंक, डिजिटल वित्तीय सेवाएँ, अप्रैल 2020।

सचेत रहेंगे और उन्हें कम करने के लिए उचित उपाय भी करेंगे। हम भुगतान प्रणालियों को तेज़, सुरक्षित, सुलभ और लचीली बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देंगे। हमने भुगतान ईकोसिस्टम और वित्तीय प्रौद्योगिकी को विनियमित करने के लिए एक नरम दृष्टिकोण अपनाया है। इन नियमों के माध्यम से, रिज़र्व बैंक इन विविध अपेक्षाओं को संतुलित करने का प्रयास करता है। हमारा दृष्टिकोण नियामक सुरक्षा नियमन स्थापित करना रहा है जिसके अंतर्गत सभी हितधारक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। हम नरम नियमों के माध्यम से सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करते रहेंगे।

जागरूकता सृजन को बढ़ावा देना

दूसरा, हालाँकि डिजिटल भुगतान के विकास, प्रसार और अपनाने में काफ़ी प्रगति हुई है, फिर भी देश में डिजिटल भुगतान को और गहरा और व्यापक बनाने की अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। जनवरी 2025 तक, भारत में लगभग 250 ट्रिलियन रुपये मूल्य के 20 अरब से ज़्यादा भुगतान डिजिटल माध्यमों से किए जा चुके थे। हममें से कई लोगों के लिए डिजिटल भुगतान, भुगतान का पसंदीदा तरीका बन गया है। हालाँकि, सर्वेक्षणों से पता चला है कि हमारी लगभग 40% वयस्क आबादी अभी भी डिजिटल भुगतान का उपयोग नहीं करती है। इसका एक मुख्य कारण डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता या जानकारी का अभाव है।

डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, हर साल मार्च में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसी प्रयास के तहत, 2023 में "हर भुगतान डिजिटल" मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों में डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और लोगों को डिजिटल भुगतान हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा और समाधान उपलब्ध कराकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। मिशन हर भुगतान डिजिटल के उद्देश्यों को सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान के उपयोग और जागरूकता में पिछड़ रहे भौगोलिक और जनसंख्या वर्गों की पहचान की जानी चाहिए और जागरूकता बढ़ाने तथा उपयोग में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

हम इस मिशन के तीसरे वर्ष में हैं। इस वर्ष का विषय है "भारत डिजिटल भुगतान करता है"। इस वर्ष भी, हम अपनी जागरूकता गतिविधियाँ जारी रखेंगे। यह दर्शाकर कि कैसे डिजिटल भुगतान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, हम उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने अभी तक डिजिटल भुगतान नहीं अपनाया है।

पिछले वर्षों की तरह, रिज़र्व बैंक इस वर्ष भी इस विषय पर मल्टीमीडिया अभियान चलाएगा। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, हम सोशल मीडिया पर आकर्षक पुरस्कारों वाली विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित करेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भी देश भर में समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करते हुए ई बात नामक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम 2012 से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में, ऐसे 1800 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इस वर्ष, ई बात की विषयवस्तु और वितरण पद्धति की समीक्षा की जाएगी, और एक पायलट प्रोजेक्ट (एक बड़े राज्य में) चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सबसे प्रभावी तरीके से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचना है।

मैं बैंकों, भुगतान प्रणाली संचालकों और अन्य हितधारकों से आग्रह करता हूं कि वे हर भुगतान डिजिटल के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अभिनव तरीकों से योगदान दें।

अधिक कुशल सीमा पार भुगतान

तीसरा, घरेलू भुगतान में यूपीआई की सफलता ने भारत को वैश्विक वास्तविक समय भुगतान में 48.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ नेतृत्व की स्थिति में पहुंचा दिया है[2], हम सीमा पार से भुगतान को और अधिक कुशल बनाने का प्रयास करेंगे। यह प्राथमिकता का विषय हो गया है क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। विश्व बैंक[3] की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि 2024 में, भारत को लगभग 130 बिलियन अमरीकी डालर का प्रेषण प्राप्त हुआ। हमें सीमा पार से भुगतान में उच्च लागत, धीमी गति और अपर्याप्त पहुंच और पारदर्शिता की चुनौतियों का समाधान करने

[2] एसीआई वर्ल्डवाइड, 2024.

[3] https://blogs.worldbank.org/en/peoplemove/in-2024--remittance-flows-to-low--and-middle-income-countries-ar

की आवश्यकता है। हम यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़कर द्विपक्षीय रूप से यूपीआई की पहुंच का विस्तार करना जारी रखेंगे। हम कुशल सीमा-पार भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई के अलावा अन्य भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की संभावना भी तलाशेंगे।[4]

पाँचवाँ डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाते हुए, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) की स्थापना के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विभाग को बधाई देता हूँ। सभी हितधारकों के सहयोग से इस विभाग द्वारा किए गए कार्यों ने भारत को डिजिटल भुगतान में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। हालाँकि, भारत की भुगतान प्रणालियों में क्रांति अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हम अभी डिजिटल भुगतान की वास्तविक क्षमता को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए नए जोश के साथ काम करते रहेंगे कि भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना रहे।

धन्यवाद।

[4] नेक्सस, जिसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है, का उद्देश्य चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) की तीव्र भुगतान प्रणालियों को जोड़ना है; और भारत, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे।